तापमान

| | | |
|---|---|---|
| भोपाल | 23.0° | 29.0° |
| इंदौर | 23.0° | 29.0° |
| जबलपुर | 24.0° | 32.0° |
| ग्वालियर | 26.0° | 36.0° |
| सागर | 24.0° | 31.0° |

# नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपालः वर्ष 41 अंक 242, पृष्ठ 12)
श्रावण, कृष्ण द्वितीया संवत् 2083
शुक्रवार, 31 जुलाई 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com
भोपाल संस्करण
भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... किसान समस्या का समाधान सरकार की सर्वोच्च ...

व्यापार... सिंधिया ने भारतीय कंपनियों से दुनिया के लिए ...

खेल... रैना बोले, अनुशासन, कड़ी मेहनत और निरंतर ...

देश-विदेश... व्हाइट हाउस में रखा एयर फोर्स वन का माडल...

## नशे के खिलाफ पीएम मोदी शुरू करेंगे 100 सप्ताह का अभियान

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले देशव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण में भागीदारी बढ़ाना है। अभियान के तहत देशभर में करीब 10 हजार स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों में एक करोड़ से अधिक युवा मादक पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ शपथ लेंगे। 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में हर रविवार विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

### अदालत ने दिल्ली सरकार को दिए निर्देश, पैलेट गन के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने से किया इनकार

# पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का कराएं इलाज : सुप्रीम कोर्ट

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः** सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों के इलाज को लेकर दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि घायल प्रदर्शनकारियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों और गोला-बारूद के इस्तेमाल से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड

सुरक्षित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस को इसके इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना कठिन होगा। अदालत ने इस मामले में पैलेट गन के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

## सीआरपीएफ प्रमुख ने बढ़ाया जवानों का हौसला बोले- निडर होकर करें काम, जिम्मेदारी मेरी

*नीट पेपर लीक के विरोध में हुए संसद मार्च के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जवानों का मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जवान बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और देशहित में लिए गए फैसलों पर भरोसा रखें। केंद्रीय बल के अलंकरण समारोह में सीआरपीएफ प्रमुख ने कहा कि चाहे अभियान से जुड़ी इकाइयां हों या कानून-व्यवस्था संभालने वाली टीमें, सभी जवान देश, जनता और बल के हित में ईमानदारी से काम करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ड्यूटी के दौरान सही भावना से लिए गए फैसलों और की गई कार्रवाइयों की जिम्मेदारी वह महानिदेशक के रूप में स्वीकार करेंगे।*

### राहत : सामान्य प्रतिभागियों पर नहीं होगी कार्रवाई

*जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी प्रदर्शन में शामिल लोगों को दिल्ली सरकार ने राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सामान्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस मामले में कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के मामले को बंद माना जाएगा और भविष्य में इसी आधार पर कोई नई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि, यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।*

## राज्यसभा में भी पास हुआ पेपर लीक संशोधन बिल, बनेगा कानून

**नई दिल्ली।** पेपर लीक रोकने से जुड़े संशोधन विधेयक को गुरुवार को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। इससे पहले यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि यह कानून केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं पर भी लागू होगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए।

### सीसीएस बैठक में हालात की समीक्षा, पीएम ने सभी मंत्रालयों को त्वरित कदम उठाने के दिए निर्देश

# ऊर्जा-उर्वरक और भारतीयों की सुरक्षा पर फोकस

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः** पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में क्षेत्रीय हालात के साथ-साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा, उर्वरक उपलब्धता और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मोदी ने सभी संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए।

### भारतीय नागरिकों और समुद्री यात्रियों की सुरक्षा पर जोर

*प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि समुद्री यात्रियों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, सहायता और आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी व्यवस्था तैयार की जाए। इसके अलावा विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई।*

### रिफाइनरियां पूरी क्षमता से कर रहीं काम

*पर्याप्त कच्चे तेल की उपलब्धता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। इससे पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों की आपूर्ति लगातार बनी हुई है। साथ ही गैस नेटवर्क, एलएनजी सुविधाओं और पाइपलाइन ढांचे के विस्तार की प्रगति की भी जानकारी दी गई।*

### आपूर्ति की समीक्षा

*बैठक में आगामी रबी सीजन के लिए उर्वरकों की मांग और उपलब्धता का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कैबिनेट सचिव ने बैठक में बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों, एलएनजी, एलपीजी और उर्वरकों की आपूर्ति फिलहाल पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात स्रोतों में विविधता लाई गई है और देश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।*

### ऊर्जा सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता पर जोरः मोदी

*प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संकटों के बीच भारत को दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने सौर ऊर्जा समेत गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार जरूरी है। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी मंत्रालयों और एजेंसियों को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों के हित सर्वोपरि हैं और उनकी सुरक्षा के साथ आवश्यक सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।*

### नेपाल में हिंसा के बाद भारत सीमा पर बढ़ी सतर्कता

***काठमांडू।*** *नेपाल के दक्षिणी हिस्से में सांप्रदायिक तनाव के बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सुनसरी और सिराहा जिलों के कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। भारत के बिहार से लगी सीमा वाले क्षेत्रों में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यह विवाद 26 जुलाई को सुनसरी जिले के कप्तानगंज क्षेत्र में शुरू हुआ था। सावन महीने में हिंदू श्रद्धालु कोशी बराज से पवित्र जल लेकर जा रहे थे। इस दौरान तेज आवाज में डीजे संगीत बजाने को लेकर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। संगीत को लेकर शुरू हुआ विवाद पहले कहासुनी और फिर हाथापाई में बदल गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। स्थिति बिगड़ने पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।*

### ईरान-अमेरिका तनाव के बीच मिस्र के बंदरगाह पर हमला

***वॉशिंगटन/तेहरान/तेल अवीव।*** *ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब मिस्र तक पहुंचता नजर आ रहा है। मिस्र के दमियाता बंदरगाह पर दो गैस टैंकरों में लगी आग को लेकर सरकार ने कहा है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि ड्रोन हमले का परिणाम थी। ड्रोन ने अमेरिकी कंपनी के प्राकृतिक गैस भंडारण टैंकर 'एनरगोस विंटर' को निशाना बनाया। हमले के बाद आग पास में खड़े दूसरे टैंकर 'गैसलॉग सलेम' तक फैल गई। घटना के बाद बंदरगाह पर मौजूद दमकल टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। रिपोर्टों में इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का दावा किया गया है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।*

## दतिया विस उपचुनाव में 71.44 प्रतिशत मतदान

**नईदुनिया ब्यूरो, दतिया :** मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में गुरुवार को मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। शाम 6 बजे तक यहां 71.4 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान करीब 9 प्रतिशत कम रहा। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह और भाजपा के आशुतोष तिवारी के बीच मुख्य मुकाबला है। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी और उसी दिन परिणाम आने की संभावना है।

### भाजपा ने विकास के मुद्दे पर मांगा समर्थन

*भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने मतदान से पहले पीतांबरा पीठ पहुंचकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने क्षेत्र के विकास, युवाओं को रोजगार और भयमुक्त माहौल की कामना की। इसके बाद उन्होंने मतदान केंद्र क्रमांक 158 पहुंचकर कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंटों से मुलाकात की। भाजपा प्रत्याशी ने दावा किया कि क्षेत्र में पार्टी के पक्ष में माहौल है और जनता विकास के मुद्दे पर समर्थन दे रही है।*

### 291 केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था

*दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां 2 लाख 20 हजार 400 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए एसएसबी समेत 16 सुरक्षा कंपनियों के 1422 जवान तैनात किए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर समय पर मतदान शुरू हुआ और प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से चल रही है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह चावला ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।*

## खास-खबरें

### पीएम के वीडियो हटाने के मामले में केंद्र सख्त

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को फेसबुक से अस्थायी रूप से हटाए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने अमेरिकी तकनीकी कंपनी मेटा के शीर्ष अधिकारियों को तलब कर इस घटना पर जवाब मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने बताया कि सरकार ने मेटा से कहा है कि वह उच्च स्तर के अधिकारियों के माध्यम से स्पष्ट करे कि आखिर यह घटना कैसे हुई।

### कावेरी जल विवाद में सीडब्ल्यूएमए का फैसला

**नईदुनिया ब्यूरो, बेंगलुरु :** कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कावेरी जल विनियमन समिति के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ा जाना है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार दो अगस्त को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी।

### हॉकी : भारतीय टीम की जर्सी पर विवाद

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली :** नई दिल्ली। हॉकी विश्व कप 2026 से पहले भारतीय टीम की नई जर्सी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हॉकी इंडिया ने टूर्नामेंट के लिए टीम की जर्सी जारी की है, जिसका रंग पारंपरिक नीले की जगह केसरिया रखा गया है। भारतीय टीम की मुख्य पहचान लंबे समय से नीले रंग की जर्सी रही है।

## भोजशाला से सटी दरगाह की जमीन पर जुमे की नमाज को सुको की मंजूरी

**नई दिल्ली/धार ब्यूरो :** सुप्रीम कोर्ट ने धार स्थित भोजशाला परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर शुक्रवार की नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि मुस्लिम समाज को शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी अन्य स्थान को आपसी सहमति से चुनने में बाधा नहीं बनेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुस्लिम समुदाय को खसरा नंबर 596 वाली जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, जिसे दरगाह की जमीन बताया

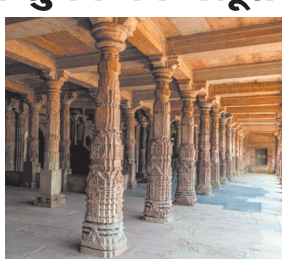

गया है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध नक्शे के अनुसार वहां पहुंचने के लिए अलग रास्ता मौजूद है और यह स्थान उपयुक्त दिखाई देता है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थान के पास शुक्रवार की नमाज के लिए अलग खुली जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था कि प्रशासन द्वारा दी जा रही जगह भोजशाला परिसर से काफी दूर है।

### मध्यप्रदेश सरकार और केंद्र के बीच हुआ समझौता, 3500 करोड़ निवेश से मिलेंगे 14 हजार रोजगार

# ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम जोन

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** मध्यप्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन स्थापित किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय और मध्यप्रदेश सरकार के बीच नई दिल्ली में समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर में बनने वाला यह टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन भारत को दूरसंचार उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहां निर्मित उपकरण देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।

### केंद्र देगा 493 करोड़ रुपये की सहायता

*परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से 493 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसमें अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं, आंतरिक अधोसंरचना, तकनीकी केंद्र और निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जोन में 5जी नेटवर्क, सैटेलाइट संचार, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सिम, राउटर और अन्य दूरसंचार उपकरणों की जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।*

### 3500 करोड़ निवेश और 14 हजार रोजगार की संभावना

*मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि उद्योग जगत के साथ हुई चर्चा में इस परियोजना में करीब 3500 करोड़ रुपये के निवेश और 14 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना सामने आई है। उन्होंने निवेशकों को ग्वालियर में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर सुविधाएं और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में निवेश करने वाली कंपनियों को कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इनमें रियायती दर पर भूमि, स्टांप शुल्क में छूट, बिजली और पानी पर विशेष सुविधाएं, पूंजीगत सब्सिडी और अनुसंधान एवं विकास सहायता शामिल हैं। मध्यप्रदेश की बेहतर भौगोलिक स्थिति, मजबूत बिजली व्यवस्था, औद्योगिक भूमि, परिवहन सुविधाएं और कुशल मानव संसाधन इस परियोजना को निवेश के लिए आकर्षक बनाएंगे।*

### 170 एकड़ में बनेगा अत्याधुनिक केंद्र

*टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन का पहला चरण 170 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। यहां प्लग-एंड-प्ले सुविधा के साथ ऐसा औद्योगिक तंत्र तैयार होगा, जहां डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, प्रमाणन और निर्यात तक की पूरी व्यवस्था उपलब्ध होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत का लक्ष्य केवल दूरसंचार उपकरणों का उपभोक्ता बनना नहीं बल्कि उनका डिजाइन, विकास और निर्माण कर दुनिया को निर्यात करना है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 'डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया' के लक्ष्य को मजबूत करेगी।*

**खुलासा** *पूर्व बस चालक के घर मिली भारी संपत्ति, नोट गिनने में लगीं पांच मशीनें भी खराब; पुलिस ने शुरू की जांच...*

# बीरभूम : छापेमारी में 28.5 करोड़ नकद और 15 किलो सोना बरामद

**नईदुनिया ब्यूरो, कोलकाता :** पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस की छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपये की नकदी और सोने का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, एक घर से 28.5 करोड़ रुपये से अधिक नकद और करीब 15 किलो सोना बरामद किया गया है। सोने की अनुमानित कीमत करीब 21.5 करोड़ रुपये बताई गई है। अधिकारियों के मुताबिक, कुल बरामदगी करीब 50 करोड़ रुपये की है। नकदी इतनी अधिक थी कि नोटों की गिनती के लिए लगाई गई पांच करेंसी गिनने वाली मशीनें भी खराब हो गईं।

### पूर्व बस चालक के घर हुई कार्रवाई

*पुलिस ने यह कार्रवाई मिनार मंडल के घर पर की। बताया जा रहा है कि मिनार मंडल पहले बस चालक थे और बाद में पत्थर कारोबार से जुड़े। वह पत्थर कारोबारी तुलु मंडल के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। तुलु मंडल को तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता अनुब्रत मंडल का करीबी माना जाता है। पूछताछ के दौरान मिनार मंडल ने दावा किया कि बरामद नकदी और सोना तुलु मंडल का है।*

### पत्थर कारोबार से जुड़े संबंधों की जांच

*पुलिस के अनुसार, मिनार मंडल का संबंध पत्थर खदानों और स्टोन क्रशर कारोबार से होने की जानकारी मिली है। हालांकि, अधिकारियों ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि छापेमारी किस मामले के आधार पर की गई थी। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि बरामद संपत्ति का किसी वित्तीय अपराध या अन्य गैर-कानूनी गतिविधि से संबंध है या नहीं।*

### पूरी रात चलती रही नोटों की गिनती

*पुलिस का तलाशी अभियान बुधवार रात शुरू हुआ था। शुरुआत में करीब 5.5 करोड़ रुपये नकद मिले थे, लेकिन गिनती आगे बढ़ने पर रकम 28 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गई। अधिकारियों ने पूरी रात बरामद रकम की गणना की। मिनार मंडल को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और क्या इसका संबंध किसी अवैध गतिविधि से है।*

### भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का दावा

*मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इस बरामदगी के बाद तुलु मंडल की बेटी की वर्ष 2024 में हुई भव्य शादी भी चर्चा में आ गई है। बताया जाता है कि उस समारोह में बड़ी संख्या में फिल्मी हस्तियां शामिल हुई थीं और शादी पर भारी खर्च किया गया था।*

## प्रियंका के बयान पर 215 कुलपति और शिक्षाविदों ने जताई आपत्ति

**नई दिल्ली।** आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की कथित 'गोमूत्र विशेषज्ञ' टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। इस मामले में 215 से अधिक कुलपतियों, पूर्व कुलपतियों और शिक्षाविदों ने संयुक्त रूप से खुला पत्र जारी कर आपत्ति जताई है। पत्र में कहा गया है कि किसी विद्वान के विचारों पर बहस करने के बजाय उसे किसी विशेष टिप्पणी या उपनाम से संबोधित करना वैज्ञानिक सोच और स्वस्थ सार्वजनिक संवाद को कमजोर करता है।